भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 573
उत्तर देने की तारीख 02 दिसम्बर, 2015

डाकघर बचत योजना

573. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव :
श्री दुष्यंत चौटाला :
श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों और सरकार द्वारा विभिन्न भारतीयों की परम्परागत पसंदीदा योजनाएं शुरू करने के बावजूद डाकघर बचत योजना लोकप्रिय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाकघरों को बैंकों के समतुल्य प्रौद्योगिकी प्रदान करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) जी, हां।

(ख) 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, लघु बचत योजनाओं के 30.86 करोड़ खाते थे, जो 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 33.03 करोड़ हो गए हैं। सरकार ने 18.11.2014 को किसान विकास पत्र (केवीपी) की पुन: बिक्री आरंभ की है तथा 31.10.2015 की स्थिति के अनुसार, डाकघरों ने 1.50 करोड़ किसान विकास पत्रों (केवीपी) की बिक्री की है, जिनमें 13293.45 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया है। उसी तरह, सरकार ने 22.01.2015 को सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की शुरुआत की थी तथा 31.10.2015 की स्थिति के अनुसार डाकघरों ने 74.21 लाख खाते खोले हैं, जिनमें 2569.41 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया है।

(ग) बैंकों की भांति, डाक विभाग ने डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), लागू किया है, स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम) संस्थापित की गई हैं तथा बचत बैंक ग्राहकों को एटीएम-कम-डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

*****